to promote this sector as a thrust industry, on the lines of gems, jewellery and info-tech. Thank you.

Need to take steps to check the spread of Japanese Encephalitis disease in various parts of the country

प्रो. एम. एम. अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी भयंकर बीमारी से 1,200 बच्चों की हुई मौतों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

यह बीमारी देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी तेजी से फैल रही है। इस संबंध में मैंने पिछले मानसून सत्र 2004 के दौरान विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया था कि वह इस भयंकर बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक व प्रभावी कदम उठाए मगर यह बड़े ही दु:ख की बात है कि देश के स्थानीय चिकित्सा अधिकारी इस बीमारी को रोकने में असफल साबित हुए हैं।

देश के जिन इलाकों में यह बीमारी फैल रही है, वहां पर न तो आवश्यक दवाइयों का इंतजाम है और न ही उच्च-स्तरीय डाक्टरों को भेजा जा रहा है। सरकार के सारे इंतजाम फेल हो चुके हैं। यही कारण है कि फिलहाल नवंबर के महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से 1,200 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। इनमें सहारनपुर में 225, मुजफ्फरनगर में 150, मेरठ में 175, बुलन्दशहर में 200, बिजनौर में 150, गाजियाबाद में 100, गौतमबुद्ध नगर में 75 तथा बागपत में 150 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी तरह से दूसरे राज्यों में यह रोग तेजी से फैल रहा है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस समस्या का समाधान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए तथा संबंधित राज्यों के अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां तथा प्रशिक्षित डाक्टरों को भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

Increase in the minimum support price of cotton in Gujarat

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात) : उपसभापति महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से कपास उत्पादक किसानों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। देश में कपास के उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है। शंकर-6 और शंकर-4 कपास के उत्पादक किसानों को कपास के दामों में गिरावट आने से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है।

महोदय, गुजरात में वर्ष 2003-2004 में कपास का उत्पादन 50 लाख गांठों का हुआ था। इस वर्ष यह उत्पादन 62 लाख गांठों का होगा। इस वर्ष दुनिया भर में कपास का उत्पादन 230.8 लाख टन होगा, जो पिछले वर्ष से 26 लाख टन ज्यादा है। कपास की मांग ज्यादा से ज्यादा 212.56 लाख टन तक ही सीमित रहेगी।

कपास की मांग से आपूर्ति ज्यादा होने की स्थिति वर्ष 2001-2002 में बनी थी। तब कपास के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत गिर गए थे। अमरीका में 1.40 करोड़ गांठों के

उत्पादन के सामने 55 लाख गांठों का ही उपयोग होने पर भी अमरीका अपने कपास उत्पादक किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी देता है जिसके कारण देश में कपास का आयात होता रहता है।

महोदय, सब्सिडी वाले सस्ते कपास का आयात न हो, इसलिए कपास पर लगे 10 प्रतिशत आयात शुल्क को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर देना चाहिए और निर्यात में ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ देना चाहिए और ब्याज दर 4 प्रतिशत कर देनी चाहिए। कपास के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य जो एक क्विंटल के लिए 1,960/- रुपए तय हुआ है, उसे बढ़ाकर 2,050/- रुपए कर देना चाहिए और सी.सी.आई. को कपास खरीदने के आदेश दिए जाने चाहिए।

महोदय, यार्न बाजार की दृष्टि से कपास में ज्यादा व्यापार को भी बढ़ावा देना चाहिए और राज्य सरकारों को सूचित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अपने कपास उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मार्गदर्शन और सहायता मिल सके।

महोदय, देश में गुजरात का कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए गुजरात के किसानों को घटते दामों से बचाकर, उनके हितों की रक्षा की जाए।

श्री शरद अनंत राव जोशी (महाराष्ट्र) : मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Need to exploit ocean resources in the country

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir,. the Department of Ocean Development is doing research for the last several years to explore the possibilities of exploiting minerals and also on-shore oil and gas recovery. But, much headway has not been shown. In the Arabian Sea and also the Indian Ocean, which is spread over to the Indian shores, more research work should be done. The country is deficient in iron ore, copper, manganese, zinc and other minerals, and the Government is importing crude oil and gas spending big amount by way of foreign exchange. Therefore, allocation may be made for ocean research for commercial use by the Government of India so that we can exploit the mineral resources and also the oil and gas available in the country. In India, we have technology and also trained engineers. The Government can utilise them for the purpose of exploiting mineral resources in this country.

Demand for intervention by the Government for retirement benefits to the Indians employed in USA

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, over 2,00,000 Indian professionals and employees, working in the USA, usually have 20 per cent of their salary deducted for social security benefits. Logically, this money should be returned to them while coming back to India. But, I